

नव भारत



5 आखिरी चरण का मतदान नया इतिहास बनाएगा - शाह



6 मालेगांव प्रकरण में जांच एजेंसियां विफल



7 भारत-न्यूजीलैंड व्यापार को नई रफ्तार



10 भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता स्वर्ण



एक नजर में

गाने विवाद में संजय दत्त ने माफ़ी मांगी

नई दिल्ली. संजय दत्त 'सरके चुन तेरी सरके' गाने को लेकर विवाद के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुए. गाने के बोलों को महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बताते हुए शिकायत की गई थी, जिसके बाद आयोग ने संज्ञान लिया. सुनवाई के दौरान संजय दत्त ने लिखित रूप में माफ़ी मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. आयोग की अध्यक्ष विजया रघटक ने कटेट के सामाजिक प्रभाव और कलाकारों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए. इस दौरान संजय दत्त ने 50 आदिवासी लड़कियों की शिक्षा का खर्च उठाने का एलान किया और भविष्य में अपने प्रोडक्ट्स में नैतिक व कानूनी जांच सुनिश्चित करने की बात कही. वहीं नोरा फतेही ने विदेश में होने के कारण अगली तारीख देने का अनुरोध किया है.

जापान में सुबह-सुबह 6.1 तीव्रता का भूकंप

टोक्यो/होकाइडो. जापान एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों से दहल उठा. जब सोमवार तड़के होकाइडो क्षेत्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया. यह झटका ऐसे समय महसूस किया गया जब अंधिकाश लोग गहरी नींद में थे, जिससे अचानक फैली दहशत ने लोगों को घरो से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया. मौसम विज्ञान के अनुसार, भूकंप सुबह 5-24 बजे स्थानीय समय पर आया और इसका केंद्र मध्य टोकाची क्षेत्र में था. मौसम विज्ञान ने बताया कि भूकंप का केंद्र मध्य टोकाची क्षेत्र में था और इसकी तीव्रता जापानी पैमाने पर '5+' दर्ज की गई. कुछ अन्य इलाकों में यह तीव्रता थोड़ी कम महसूस की गई, लेकिन झटके इतने मजबूत थे कि लोगों में डर का माहौल बन गया.

पद्म पुरस्कार 2027 नामांकन प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार-2027 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है. 15 मार्च 2026 से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, जबकि अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. सभी नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिनकी शुरुआत 1954 में हुई थी और हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं. ये सम्मान कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, विज्ञान, समाज सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं. सरकार 'पीपल्स पद्म' पहल के तहत आम नागरिकों से अधिक से अधिक नामांकन करने की अपील कर रही है.

गुस्ताखी माफ़



बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

'नारी शक्ति वंदन' संकल्प मध्यप्रदेश विधानसभा में ध्वनिमत से पारित



विशेष संवाददाता भोपाल, 27 अप्रैल. संसद में 17 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल गिराने के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें 'नारी शक्ति वंदन' संकल्प को पारित किया गया. मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को महिला आरक्षण के मुद्दे ने सियासी तापमान बढ़ा दिया. सरकार द्वारा पेश 'नारी शक्ति वंदन' संकल्प पर चर्चा के दौरान विपक्षी कांग्रेस और



सत्तापक्ष आमने-सामने आ गए, जिसके चलते सदन में तीखा हंगामा हुआ और अंततः कांग्रेस ने बाकआउट कर दिया. विपक्ष के बाहर जाने के बाद सरकार ने अपना प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित करा लिया.

सत्र की शुरुआत शोक संदर्भों के साथ हुई, लेकिन इसके बाद माहौल तेजी से राजनीतिक टकराव में बदल गया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब सदन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के समर्थन में संकल्प

पेश किया और इसके क्रियान्वयन को जनगणना व परिसीमन से जोड़ा, तभी विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस प्रक्रिया को अनावश्यक देरी बताते हुए तत्काल प्रभाव से

विवाद बढ़ने पर कांग्रेस सदस्य वेल में पहुंच गए और सरकार से स्पष्ट समयसीमा बताने की मांग करने लगे. जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सामूहिक रूप से सदन से बहिर्गमन कर दिया, जिससे कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही. कांग्रेस के बाहर जाने के बाद सत्तापक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही आरक्षण लागू करेगी. संसदीय कार्य मंत्री केशवा विजयवर्गीय ने भी यही रुख दोहराते हुए महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता जताई. विपक्ष की अनुपस्थिति में सरकार को सदन में बहुमत का लाभ मिला और 'नारी शक्ति वंदन' संकल्प बिना किसी बाधा के पारित हो गया.

मौजूदा सौदों पर आरक्षण लागू करने की मांग उठाई.

ओबीसी आरक्षण पर याचिका करें अलग-अलग

जबलपुर, 27 अप्रैल. मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार से तीन दिनों तक लगातार सुनवाई प्रारंभ हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने ओबीसी आरक्षण के पक्ष तथा विपक्ष में दायर याचिकाओं को अलग-अलग करने के निर्देश जारी किये हैं. याचिकाओं पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी. गौरतलब है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के पक्ष तथा विपक्ष में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी तथा मराठा आरक्षण के संबंध में दायर याचिकाओं में स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिये। कुछ याचिकाओं में फार्मूला 87:13 को चुनौती देते हुए 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर आपत्ति की गयी थी. पक्ष में दायर की गयी याचिकाओं में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग की गयी थी. हाईकोर्ट ने कुछ याचिकाओं की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद प्रदेश सरकार सहित अन्य पक्षकारों ने सर्वोच्च न्यायालय में इसी मुद्दे पर एसएलपी दायर की थी. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी एसएलपी को सुनवाई के लिए वापस हाईकोर्ट भेज दिया था.

वरिष्ठ अधिकाता आदित्य संधी ने युगलपीठ को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने तीन माह में संबंधित याचिकाओं के निराकरण करने निर्देश जारी किये हैं. युगलपीठ को याचिका की सुनवाई के दौरान जानकारी दी गयी कि ओबीसी आरक्षण के विपक्ष में 70 तथा पक्ष में 30 याचिकाएं दायर की गयी हैं. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद तर्क प्रस्तुत करने के लिए पक्ष व विपक्ष में दायर याचिकाओं को अलग-अलग करने आदेश जारी किये.

8 स्टेशनों पर रुकेगी नई अमृत भारत ट्रेन

मग्न के रेल यात्रियों के लिए सुखखबरी



जिससे श्रद्धालुओं और आम यात्रियों के लिए सफर बेहद किरफायती और आसान हो जाएगा. रेलवे द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक बनारस - पुणे(हड़पसर) अमृत भारत एक्सप्रेस का सीधा लाभ मध्य प्रदेश के यात्रियों को मिलेगा. ये दोनों ट्रेनों मध्य प्रदेश के प्रमुख जंक्शनों से होकर गुजरेंगी,

अयोध्या-मुंबई (एलटीटी) अमृत भारत एक्सप्रेस प्रदेश के सतना, जबलपुर और इटारसी से होकर गुजरेंगी, जिससे श्री राम जन्मभूमि व अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का दर्शन का राह आसान हो जाएगा. यह ट्रेन पूरी तरह से गैर-वातानुकूलित है, जिसमें 12 जनरल और 8 स्लीपर कोच शामिल हैं. इसमें 90पुंश-पुल 6 तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह तेजी से रफ्तार पकड़ती है और समय बचाती है. प्रधानमंत्री वाराणसी जंक्शन-पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन तीसरी और चौथी रेलवे लाइन परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसमें 2,642 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में गंगा नदी पर नया रेल सह सड़क पुल भी शामिल है.

ईरान सीजफायर करे नहीं तो गैस पाइप लाइन उड़ा देंगे

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दिया तीन दिन का अल्टीमेटम

वॉशिंगटन/तेहरान, 27 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीजफायर पर सहमत होने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने युद्ध विराम नहीं किया, तो उसकी तेल पाइपलाइनों को उड़ा दिया जाएगा.



अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध और उससे जुड़े कटनीतिक गतिरोध पर अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति सलाहकारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फिलहाल ठहराव की स्थिति में पहुंच गयी है. अमेरिकी मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ अगले कदमों के विचार करेंगे. अधिकारियों के अनुसार, ईरान द्वारा हाल में प्रस्तुत नये प्रस्ताव को अमेरिका की प्रमुख शर्तों के अनुरूप नहीं माना गया.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध और उससे जुड़े कटनीतिक गतिरोध पर अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति सलाहकारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फिलहाल ठहराव की स्थिति में पहुंच गयी है. अमेरिकी मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ अगले कदमों के विचार करेंगे. अधिकारियों के अनुसार, ईरान द्वारा हाल में प्रस्तुत नये प्रस्ताव को अमेरिका की प्रमुख शर्तों के अनुरूप नहीं माना गया.

ईरानी विदेश मंत्री ने पुतिन से की मुलाकात

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघावी ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसमें रूस ने खुले तौर पर ईरान के प्रति समर्थन जताया. पुतिन ने कहा कि ईरानी जनता साहस और वीरता के साथ अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता का संदेश प्राप्त हुआ है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच हालिया बातचीत किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है.

बंगाल में चुनाव प्रचार थमा

आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी

142 सीटों पर कड़ी सुरक्षा में होगा मतदान 1400 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में

कोलकाता, 27 अप्रैल. पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया. इसके साथ ही 48 घंटे का साइलेंट पीरियड लागू हो गया है. अब 29 अप्रैल को राज्य की 142 सीटों पर मतदान कराया जाएगा, जिसमें नदिया, हावड़ा, हुगली और कोलकाता सहित कई जिले शामिल हैं.

प्रचार के अंतिम दिन नरेंद्र मोदी ने उत्तर 24 परगना के जगतदल में रेली कर भाजपा की जीत का दावा किया. वहीं अमित शाह ने बेहाला में रोड शो कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा दिलाया. इस चरण में कुल 1,448 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें और स्पष्ट विवरण देने की व्यवस्था की है. मतदान को शांतिपूर्ण बनाने के लिए केंद्रीय बलों को 2,407 कंपनियों तैनात की गई हैं. इसके अलावा राज्य पुलिस भी अलर्ट पर है. राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है.

आप के 7 सांसदों को भाजपा में विलय की मंजूरी

बीजेपी की सदस्य संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई

आप पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर तीन हो गई

नई दिल्ली, 27 अप्रैल. राज्यसभा के सभापति ने सदन के उन सात सदस्यों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय की मंजूरी दे दी है जो हाल में आम आदमी पार्टी (आप) से अलग हो गए हैं. राज्यसभा सचिवालय द्वारा सोमवार को जारी सदन में विभिन्न दलों की सदस्य सूची में आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल होने की घोषणा करने वाले सदस्यों के नाम भाजपा की सूची में आ गए हैं और पार्टी की सदस्य संख्या 106 से बढ़कर



113 हो गई है. उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी से निर्वाचित सदस्य राघव चड्ढा, डॉ संदीप कुमार पाठक और डॉ अशोक कुमार मिश्र ने 24 अप्रैल को राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन कर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सात सदस्यों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल

होने की घोषणा की थी. इन सदस्यों में उपरोक्त तीन के अलावा हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं. इस सूची में आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर तीन हो गई है. राज्यसभा सचिवालय की ओर से आजाद सचिवालय के अनुसार इन सदस्यों को 24 अप्रैल से ही भाजपा के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है.

बंगाल की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं पीछे नहीं हटूंगा

बैरकपुर, 27 अप्रैल. पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में सोमवार को विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की राजनीति, विकास और आगामी चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में जहां-जहां वे गए, वहां लोगों का उत्साह और अपनापन उन्हें गहराई से प्रभावित कर रहा है. 4 मई के चुनाव परिणामों के बाद भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें फिर से बंगाल आने का

प्रेरित कर रही है. जब भारत समृद्ध था, तब अंग, बंग और कर्लिंग जैसे क्षेत्र उसकी शक्ति का आधार थे और आज देश को विकसित बनाने के लिए इन क्षेत्रों का मजबूत होना जरूरी है. वहीं पीएम ने कहा मजदूरों और किसानों के साथ हैं और

बंगाल में प्रथम चरण के वोटिंग में युवाओं और महिलाओं ने मजबूती दी. पीएम मोदी ने बताया कि हाल की रैलियों के दौरान उन्हें जनता का अभूतपूर्व प्रेम और समर्थन देखने को मिला, जिससे उनका उत्साह और बढ़ गया है. उन्होंने एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि एक महिला समर्थक उनसे मिलने के लिए बैरिकेड्स पार करने की कोशिश कर रही थी, जो उनके लिए भावनात्मक क्षण था. प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर भी निशाना साधा.

मतदान से पहले पीएम मोदी का संदेश नई दिल्ली से नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के नाम आडियो संदेश जारी किया. दूसरे चरण के मतदान से पहले उन्होंने जनता का आभार जताते हुए 29 अप्रैल को मतदान करने की अपील की. मोदी ने कहा कि बंगाल में चुनाव अभियान के दौरान उन्हें जबरदस्त ऊर्जा और समर्थन मिला. उन्होंने इसे एक 'धार्मिक यात्रा' जैसा अनुभव बताया और कहा कि जनता का स्नेह ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है.

लद्दाख में बनेंगे 5 नए जिले

लेह/नई दिल्ली, 27 अप्रैल. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पांच नए जिलों के गठन की मंजूरी दे दी है, जिससे लंबे समय से चल रही स्थानीय लोगों की मांग पूरी हो गई है। नए जिलों में नुबा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास शामिल हैं। इन जिलों के गठन के बाद लद्दाख में कुल जिलों की संख्या बढ़कर सात हो जाएगी, जबकि अब तक यहां केवल लेह और कारगिल ही जिले थे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक सरकारी सेवाएं तेजी से पहुंच सकेंगी. खासकर

दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब अपने काम के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। यह कदम न केवल प्रशासन को लोगों के करीब लाएगा, बल्कि क्षेत्र में विकास, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा करेगा. ये सभी क्षेत्र भौगोलिक रूप से विशाल और दुर्गम हैं, जहां लोगों को अब तक प्रशासनिक कामों के लिए लेह या कारगिल जाना पड़ता था

